

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27.06.15 को सिंचाई खण्ड सिंचाई पी०एम०जी०एस०वाई० देहरादून (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जे.पी. बिज्जनायक एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री डी.के. सेनी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आदर तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 780 (मी०) नाप भूमि से, 820 (मी०) सिविल भूमि से, 450 (मी०) वन पंचायत से, 6075 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7020 है० नाप भूमि 0.5740 है० सिविल भूमि 0.3150 है० वन पंचायत 4.2525 है० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.1415 है० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 1.82 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 4.6 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे। ग्रामीणों के अत्याधिक विवाद के कारण दूसरा समरेखण नहीं किया जा सका।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 800 (मी०) नाप भूमि से, 900 (मी०) सिविल भूमि से, 500 (मी०) वन पंचायत से, 6300 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.7200 है० नाप भूमि 0.6300 है० सिविल भूमि 0.3500 है० वन पंचायत भूमि 4.4100 है० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.390 है० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 2.89 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 7.8 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78° 09' 43.59" E 30° 19' 31.68" N है तथा यह स्थल मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कुण्ड है जिसका GPS मान 78° 12' 33.58" E 30° 18' 40.34" N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संन्तलग्न हैं। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु कृषकों की भूमि पर खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78° 10' 01.68" E 30° 19' 02.86" N, 78° 10' 00.11" E 30° 19' 00.59" N, 78° 11' 13.49" E 30° 19' 29.32" N, 78° 11' 14.51" E 30° 19' 31.57" N, 78° 11' 18.63" E 30° 19' 32.37" N, 78° 11' 17.78" E 30° 19' 30.87" N, 78° 11' 21.09" E 30° 19' 20.92" N, 78° 11' 22.17" E 30° 19' 12.51" N, 78° 11' 15.62" E 30° 18' 30.37" N हैं।

हस्ताक्षर
प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

हस्ताक्षर
वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
जोतांशी
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

उप प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेंज

उप वन क्षेत्राधिकारी
घनोस्टी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून

Joint inspection

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.M.G.S.Y, Irrigation Division-2, New Tehri, for "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) " under FCA-1980 of 5.1415 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) ". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 12-07-2016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 3.5525 ha.(MFD) + RF 0.7000 ha.(NNFD)=4.2525ha.+ PF 0.00 ha.+CF 0.889 ha. = 5.1415 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area. If so the details there of: No.

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, If so the details there of with NOC from compentent authority, if required:- No.

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.(√)
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)] Act 1980 provided. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation)] Act 1980 is attached.(x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Proposal is recommended.

(Signature)

Place - Mussoorie

Name (Dr. Dheeraj Pandey)

Date - 18.7 . 2016

Designation. प्रभागीय वनाधिकारी
मुसुरी वन प्रभाग, मुसुरी.

Office Seal

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.